लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 252
दिनांक 04 फरवरी, 2025 / 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भारतपोल पोर्टल

252. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसाबा:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री शंकर लालवानी
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री विजय बघेल:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागोरी:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री तापिर गाव:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. भोला सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज करने के लिए हाल ही में बनाये गए/ शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास भारतपोल पोर्टल की क्षमताओं को आपराधिक जांच से परे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने जैसे कार्यों में शामिल करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में भारतपोल प्रणाली का उपयोग कर रहे/ इसमें समेकित किये गए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) पोर्टल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों और जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदान किए जा रहे/कार्यान्वित किये जा रहे तकनीकी प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या पोर्टल से अपराध समाधान दरों और आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उलेखनीय सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 252, दिनांक 04.02.2025

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ड): केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 07.01.2025 को भारतपोल पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के मॉड्यूल अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों के प्रवासियों और हथियारों की तस्करी, संगठित साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी, आतंकवाद और अन्य से संबंधित आपराधिक मामलों में विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में, भारतपोल पोर्टल में निम्नलिखित पांच मॉड्यूल हैं:

(1) कनेक्ट मॉड्यूल: यह सीबीआई को भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भारत में सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक ही मंच पर जोड़ता है।

(2) ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल: विदेशों द्वारा साझा की गई सहायता या आपराधिक खुफिया जानकारी के लिए विदेशों से अनुरोध भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई या जानकारी के लिए प्रेषित किए जा सकते हैं।

(3) इंटरपोल संदर्भ मॉड्यूल: यह विदेशों में जांच के लिए भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल चैनलों के माध्यम से तेजी से अंतरराष्ट्रीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है।

(4) इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल: यह भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल नोटिस के अनुरोधों के तेज, सुरक्षित और संरचित प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है।

(5) संसाधन मॉड्यूल: यह प्रासंगिक दस्तावेजों और क्षमता निर्माण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।

भारतपोल पोर्टल के कनेक्ट मॉड्यूल के माध्यम से, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के इंटरपोल संपर्क अधिकारी (आईएलओ) सीबीआई से जुड़े हुए हैं और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी यूनिट अधिकारी (यूओ) केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां संबंधित आईएलओ से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में, इस पोर्टल के माध्यम से, 51 कानून प्रवर्तन एजेंसियां (अनुबंध 1) और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 500 से अधिक यूनिट कार्यालय जुड़े हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग और भारतपोल पोर्टल पर सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (आईएलओ) के लिए 07.01.2025 (दोपहर) को सीबीआई मुख्यालय में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता के लिए आने वाले महीनों में पोर्टल के उपयोग के संबंध में व्यक्तिगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी इस पोर्टल के बारे

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 252, दिनांक 04.02.2025

में जागरूकता पैदा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच इसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।

भारतपोल पोर्टल ने इंटरपोल नोटिसों के प्रकाशन और इंटरपोल संदर्भों के माध्यम से आपराधिक मामलों में सहायता के अनुरोध के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त करना शुरू कर दिया है। 07.01.2025 को पोर्टल के शुभारंभ के बाद से इस पोर्टल के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन के लिए सोलह (16) अनुरोध प्राप्त हुए हैं और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता मांगने वाले आठ (08) इंटरपोल संदर्भ प्राप्त हुए हैं। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता मांगने वाले विदेशों से प्राप्त तीस (30) अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को इस पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 252, दिनांक 04.02.2025

अनुबंध 1

भारतपोल से जुड़े इंटरपोल संपर्क अधिकारी (आईएलओ) की सूची

क्रमसं.	राज्य
1	केंद्रीय जांच ब्यूरो
2	लद्दाख पुलिस
3	झारखंड पुलिस
4	असम पुलिस
5	तेलंगाना पुलिस
6	गोवा पुलिस
7	कोलकाता पुलिस
8	गुजरात पुलिस
9	प्रवर्तन निदेशालय
10	राजस्थान पुलिस
11	एन.सी.आर.बी.
12	पंजाब पुलिस
13	ओडिशा पुलिस
14	मध्य प्रदेश पुलिस
15	आंध्र प्रदेश पुलिस
16	दिल्ली पुलिस
17	मेघालय पुलिस
18	छत्तीसगढ़
19	हरियाणा
20	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.)
21	केरल पुलिस
22	त्रिपुरा पुलिस
23	महाराष्ट्र पुलिस
24	जम्मू और कश्मीर पुलिस
25	चंडीगढ़ पुलिस
26	अंडमान और निकोबार पुलिस
27	कर्नाटक पुलिस
28	मणिपुर पुलिस
29	राजस्व आसूचना निदेशालय

// जारी..

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 252, दिनांक 04.02.2025

अनुबंध 1 (जारी)

30	सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए)
31	एम.ए.सी., इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय
32	आप्रवासन ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली
33	सी.आई.एस.एफ.
34	तटरक्षक बल
35	आई.टी.बी.पी.
36	उत्तराखंड पुलिस
37	भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केन्द्र (आई4सी)
38	मुंबई पुलिस
39	उत्तर प्रदेश पुलिस
40	नागालैंड पुलिस
41	राष्ट्रीय जांच एजेंसी
42	हिमाचल प्रदेश पुलिस
43	अरुणाचल प्रदेश पुलिस
44	पश्चिम बंगाल पुलिस
45	सिक्किम पुलिस
46	रेलवे सुरक्षा बल
47	सशस्त्र सीमा बल
48	सीमा सुरक्षा बल
49	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
50	बिहार पुलिस
51	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण